

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 मई 2012—ज्येष्ठ 5, शक 1934

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011.—छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, पीपुल्स लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ इण्डिया (पी.एल.एफ.आई.) एवं तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टी.पी.सी.) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए तत्काल प्रभाव से विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2012

क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 26-05-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 26th May 2012

NOTIFICATION

No. F-4-195/Home-C/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006), the State Government, hereby, declares the Peoples Liberation Front of India (P.L.F.I.) and Tiritiya Prastuti Committee (T.P.C.) as Unlawful Organisations with immediate effect for a period of one year from the date of issue of this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.